BSNL EMPLOYEES UNION

Recognised Union in BSNL
(Registered Under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No.4896)
CHQ:Dada Ghosh Bhawan, Opp. Shadipur Bus Depot., New Delhi – 110008
Email: bsnleuchq@gmail.com, website: bsnleuchq.com

P. Abhimanyu
General Secretary

Phone: (O) 011-25705385
Fax : 011-25894862

बीएसएनएलईयू/102(सरकुलर संख्या 17)

29, नवम्बर, 2016

सेवा में,
सभी सर्किल सचिव,
सी एच क्यू पदाधिकारी
और जिला सचिव

एक दिवसीय हड़ताल को पूर्ण रूप से सफल बनाओ

बीएसएनएल की यूनियनों और एसोसिएशनों ने एक सहायक टॉवर कंपनी बनाने के सरकार के क़दम के ख़िलाफ़ एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है जो 15–12–2016 को होगी। ख़बर है कि माननीय संचार राज्य मंत्री ने पहले ही कैबिनेट नोट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसे अब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है । बीएसएनएल के नॉन–एक्जिक्यूटिवों और एक्जिक्यूटिवों ने सरकार के सहायक टॉवर कंपनी बनाने के इरादे के खिलाफ पिछले दो सालों में फोरम के बैनर तले कई संघर्ष चलाए हैं । किंतु सरकार ने बीएसएनएल कर्मचारियों के विरोध की उपेक्षा करना पसंद किया है और सहायक टॉवर कंपनी बनाने के लिए आगे बढ़ी है । सरकार ने कर्मचारियों को यह समझाना भी जरूरी नहीं समझा कि वह सहायक टॉवर कंपनी क्यों बनाने जा रही है। इन परिस्थितियों में कर्मचारियों के पास संघर्ष पर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। 27–10–2016 को प्रदर्शन किए गए और 25–11–2016 को देशव्यापी धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएनएल की रक्षा के लिए 15–12–2016 को एक दिवसीय हड़ताल आयोजित की जा रही है जिसे 100 प्रतिशत सफल बनाना है।

सहायक टॉवर कंपनी क्या है?

इस समय बीएसएनएल के पास लगभग 65,000 मोबाइल टॉवर हैं। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इन सभी मोबाइल टॉवरों को बीएसएनएल से ले लिया जाएगा और एक अन्य कंपनी को सौंप दिया जाएगा जिसका सरकार गठन करना चाहती है। इस कंपनी का नाम सहायक टॉवर कंपनी रखा जाएगा। बीएसएनएल प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीएसएनएल इस कंपनी की मालिक होगी और वही इसका प्रबंधन करेगी। इस सहायक टॉवर कंपनी को चलाने के लिए बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के एक हिस्से को इस कंपनी में लगाया जाएगा।

सहायक टॉवर कंपनी के पक्ष में तर्क

(1) यह तर्क दिया जा रहा है कि टेलीकॉम उद्योग में टॉवर बिजनेस एक बहुत ही लाभकारी बिजनेस है। किंतु बीएसएनएल अपनी ही टॉवरों का पूरा उपयोग नहीं कर पाती और अधिकतम लाभ नहीं कमा पाती है। अगर एक अलग टावर कंपनी बना दी जाती है तो प्रबंधन अपना ध्यान टॉवर बिजनेस पर केंद्रित कर सकेगा और टॉवरों के प्रबंधन का काम अधिक कुशलता के साथ किया जा सकेगा और लाभ भी अधिकतम कमाया जा सकेगा।

(2) बीएसएनएल इस लिए घाटे में चल रही है चूंकि इसके मूल्यह्रास की राशि बहुत अधिक है। वर्ष 2015–16 के लिए मूल्यह्रास की राशि 8,816 करोड़ रूपये थी। तर्क यह है कि इस मूल्यह्रास का एक बड़ा हिस्सा सहायक टावर कंपनी के गठन के बाद उसके खाते में चला जाएगा। इसके फलस्वरूप बीएसएनएल के एक लाभ कमाने वाली कंपनी बनने के चांस भी बढ़ जाएंगे।

भ्रामक तर्क

यह भ्रामक और धोखाधड़ीपूर्ण तर्क है कि अगर एक सहायक टॉवर कंपनी का गठन कर दिया जाता है तो टॉवर बिजनेस अधिक लाभकारी हो जाएगा। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार सहायक टॉवर कंपनी भी बीएसएनएल द्वारा तैनात किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ही चलाई जाएगी। अगर वही कर्मचारी और अधिकारी सहायक टॉवर कंपनी को अधिक

लाभ में चलाने के लिए टॉवर बिजनेस की व्यवस्था कर सकते हैं तो वे बिना सहायक टॉवर कंपनी बनाए भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए, एक सहायक टावर कंपनी बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

यह सभी को ज्ञात है कि बीएसएनएल सिर्फ सरकार की बीएसएनएल–विरोधी और निजी कंपनी समर्थक नितियों के कारण घाटे में गई है। भूतपूर्व टेलीकॉम मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद के वयान के अनुसार बीएसएनएल को यूपीए के शासन काल में लगभग दस सालों तक उसके विस्तार की इजाजत नहीं दी गई। मूल्यह्रास की भारी राशि को बीएसएनएल के घाटे का कारण बताना अस्वीकार्य है। बीएसएनएल ने प्रबंधन और कर्मचारियों की संयुक्त मेहनत के कारण पहले ही बहुत अच्छा सुधार दिखाना शुरू कर दिया है। यह निश्चित है कि बीएसएनएल बिना एक सहायक टॉवर कंपनी बनाए भी फिर से एक लाभ कमाने वाली कंपनी बन जाएगी।

सहायक टॉवर कंपनी बनाना बीएसएनएल का पिछले दरवाजे से निजीकरण करने का तरीका है।

इस प्रकार, सरकार का एक अलग टॉवर कंपनी बनाने का इरादा बीएसएनएल की इसके टॉवर विजनेस के अधिक कुशलतार्पूक प्रबंधन करने में मदद करने का नहीं है। तब असली इरादा क्या है? बीएसएनएल के गठन से लेकर उत्तरोत्तर सरकारों ने बीएसएनएल में विनिवेश शुरू करने और उसका निजीकरण करने की भरसक कोशिश की है। किंतु, बीएसएनएल के संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन ने उन सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। टेलीकॉम उद्योग में बीएसएनएल ही अकेला पी एस यू है जो एक 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी है। वीएसएनएल का पहले ही निजीकरण हो चुका है। एमटीएनएल में पहले ही 46.5 प्रतिशत विनिवेश किया जा चुका है। इसलिए, सरकार बीएसएनएल में बेसबरी के साथ विनिवेश शुरू करना चाहती है। सहायक टॉवर कंपनी का गठन करना बीएसएनएल का पिछले दरवाजे से निजीकरण करने के तरीके के अलावा और कुछ नहीं है।

कर्मचारी सरकार के मीठे शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे कि सहायक टॉवर कंपनी 100 प्रतिशत सरकारी कंपनी रहेगी और बीएसएनएल उसकी संपूर्ण मालिक होगी। वर्तमान सरकार की नीति जितना जल्दी हो सके सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों का निजीकरण करने की है। यह एक खुला रहस्य है कि नीति आयोग का पूर्णकालिक काम सार्वजनिक कंपनियों के निजीकरण का खाका तैयार करना है। अगर सहायक कंपनी के गठन की इजाजत दी गई तो बहुत जल्द ही रणनीतिक बिक्री शुरू हो जाएगी और एक निजी पार्टनर रख लिया जाएगा। उसके बाद वे दिन दूर नहीं होंगे जब सहायक टॉवर कंपनी का पूरा निजीकरण कर दिया जाएगा। वर्तमान स्थिति में बीएसएनएल की मोबाइल टॉवर उसकी जीवन रेखा हैं। अगर बीएसएनएल से उसकी टॉवर ले ली जातीं हैं तो बीएसएनएल स्वयं अपनी मौत मर जाएगी। इसलिए, हम सरकार को बीएसएनएल से उसकी बहुमूल्य मोबाइल टॉवर छीनने की इजाजत नहीं देंगे।

बीएसएनएल के गठन के समय ये ही संयुक्त ट्रेड़ यूनियन आंदोलन बीएसएनएल को सरकार के हमलों से बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। कर्मचारियों ने सरकार द्वारा अनबंडलिंग, विनिवेश, वीआरएस, आदि के लिए उठाए गए कदमों को सफलतापूर्वक रोका है। वर्तमान स्थिति में भी कर्मचारी सहायक टॉवर कंपनी के गठन के माध्यम से बीएसएनएल को खत्म करने की नापाक योजना को निश्चित रूप से शिकस्त देंगे।

एक दिवसीय संपूर्ण हड़ताल को पूरी तरह सफल बनाओ!

मजदूर एकता जिंदाबाद!!

बीएसएनएल जिंदाबाद!!

(पी अभिमन्यु)
जनरल सेक्रेट्री